4. ऐसे एक्सचेंजों के खोलने में किराये पर उचित भवन और एक्सचेंज उपस्कर, पावर संयंत्र, बैटरी, केबल, लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है। अतः एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की आवंटित निधियों का उपयोग करना

1557. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दी गई पूरी धनराशि का उपयुक्त ढंग से उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को बिजली दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मार्च, 1981 के अन्त तक 58 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के खाते में ये दर्ज हुये हैं। इसकी तुलना में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उस दिन तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कुल 103.31 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। 45 करोड़ की शेष राशि में 12 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है जो मार्च, 1981 में वितरित की गई थी और भंडार में पड़ी हुई निर्माण सामग्री की लागत शामिल है जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जाएगा। सम्पन्न हुये निर्माण कार्यों के पूरा होने की रिपोर्ट जब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार कर ली जायेगी तब 31 मार्च, 1981 तक हुआ वास्तविक व्यय ऊपर बताये गये खर्चे से अधिक होने की संभावना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम निर्माणाधीन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग नियमित रूप से करता रहा है ताकि उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायताओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उत्तर प्रदेश में, 1,12,561 गांव हैं जिन में से 38,577 गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में विद्युतीकृत कर दिया गया था। यह संख्या 38 प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण को दर्शाती है। छठी योजना अवधि (1980–85) के दौरान, उत्तर प्रदेश में लगभग 33000 और गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है, जिस में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले 18000 गांव शामिल हैं। आशा की जाती है कि छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता लगभग 63 प्रतिशत हो जाएगी।

Re-instatement of Orissa T.V. Centre Employees

1558. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of employees working on different posts in the T.V. Centres of Orissa whose services were terminated during the last three years;

(b) the reasons for the termination of their services;

(c) whether the proposals for their re-instatement are under the consideration of Government; and

(d) if so, the expected time of taking a decision in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) Nil.

(b) to (d). Does not arise.